



दिल्ली पुलिस के नोटिस का राहुल जल्द देंगे जवाब

एनसीआर समाचार

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास पर रविवार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर सागर प्रीत हुड्डा पहुंचे, जहां कुछ घंटों के इंतजार के बाद उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को श्रीनगर में दिए बयान के संबंध में नोटिस सौंपा। नोटिस का जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने समय मांगा है। स्पेशल सीपी (लॉ एंड ऑर्डर) सागर प्रीत हुड्डा ने रविवार को कहा, "हम राहुल गांधी से बात करने आए हैं। राहुल गांधी ने 30 जनवरी को श्रीनगर में बयान दिया था कि यात्रा के दौरान वे कई महिलाओं से मिले। महिलाओं ने उन्हें बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ है। हम उनसे थ्योरा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।"

हुड्डा ने बताया कि उनसे सांसद राहुल गांधी की मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया कि यात्रा लंबी थी और यात्रा को पूरा हुए भी काफी समय हो गया है। उन्हें सब दोबारा दोहराना होगा। राहुल ने आश्वासन दिया कि वे जल्द ही अपना जवाब देंगे। उनसे जवाब मिलने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में 30 जनवरी को कहा था कि उन्हें यात्रा के दौरान कई महिलाएं रोती हुई मिलीं, जिन्होंने उन्हें बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ है। राहुल के इस बयान पर नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस ने उनसे यह पूछा है कि हमें उन तमाम महिलाओं के बारे में जानकारी दें, ताकि हम कार्रवाई कर सकें।



राहुल को नोटिस देने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को भारी झुामा देखने को मिला, जब दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए उनके भाषण को लेकर नोटिस दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उनमें से कुछ को पुलिस ने शहर की कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में हिरासत में लिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को कश्मीर में उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाओं पर उत्पीड़न के संबंध में दिए गए भाषण के लिए पुलिस ने नोटिस जारी किया था। इसके तुरंत बाद, तुगलक लेन इलाके में उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस और केेंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। मामले की गंभीरता को भांपते हुए सुबह अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वह केवल महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि कुछ महिलाएं उनसे मिलीं और आरोप लगाया कि उनका यौन उत्पीड़न किया गया।

भाजपा सबसे बड़ी पार्टी लेकिन ताकत को और चार गुना बढ़ाना है : जेपी नड्डा

चंडीगढ़, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को समालखा के पट्टी कल्याण में स्थित सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र में पार्टी के शक्ति केंद्र संगम में कहा कि अभी हमें अपनी ताकत को चार गुणा और बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि यह सही है कि विरोधी भी मान रहे हैं कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन इससे हमें रुक नहीं जाना है बल्कि इस शक्ति को अभी चार गुणा और अधिक बढ़ाना है। नड्डा ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं-पदाधिकारियों को अब तक किये जा रहे कार्यों के लिए साधुवाद दिया। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई आईडियोलॉजी नहीं है। वे परिवार से अधिक सोच नहीं पाते लेकिन हम सिद्धांतों वाली पार्टी हैं। इसलिए हमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करते हुए आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र ने विश्व में भारत का जो नाम किया है उस यश को और भी अधिक बढ़ाना है।

उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा वर्तमान में हरियाणा में जिस तरीके से काम कर रही है, उस हिसाब से जल्द ही पार्टी वर्तमान के मुकाबले आने वाले समय में चार गुणा अधिक और अधिक बढ़ेगी। नड्डा ने उपस्थित



कार्यकर्ताओं से कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं को पढ़कर सभी कार्यकर्ता याद रखें और जनता के बीच जाकर इस संबंध में बात करें। लोगों को बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी ने नेतृत्व में देश दुनिया में कितना आगे बढ़ा है। उन्होंने इस अवसर पर केंद्र सरकार की अनेक गरीब कल्याण की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता की मेहनत रंग ला रही है।

इससे पहले हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बताया कि प्रदेश में अब तक पार्टी पन्ना प्रमुख तक का कितना काम संपन्न कर चुकी है।

संसद का पूरा सप्ताह शोरगुल, हंगामे की भेंट चढ़ा

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले सप्ताह में विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों के भारी हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक अभी मात्र 66 मिनट चली वहीं राज्यसभा कुल 159 मिनट ही चल पाई। संसद के बजट सत्र में सोमवार को दूसरे चरण में प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत के लोकतंत्र के बारे में लंदन में दिए गए बयान पर माफी मांगने की मांग पर अड़े हुए हैं जबकि कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल अडाणी समूह से जुड़े मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने पर जोर दे रहे हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण पूरा सप्ताह लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही बाधित रही और अन्य कामकाज भी नहीं हो सका। पूरे सप्ताह के दौरान हंगामे के बीच ही लोकसभा में 17 मार्च को सबसे अधिक 20 मिनट बैठक चली जबकि 16 मार्च को सबसे कम तीन मिनट कार्यवाही चली। विधायी कार्य के तहत 13 मार्च को सदन में वर्ष 2022-23 के अनुदान की अनुसूचक मांग के दूसरे बैच



का दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू कश्मीर की अनुदान की मांग पेश की गई। वहीं 15 मार्च को रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने निचले सदन में अंतर सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक 2023 पेश किया। इस प्रकार लोकसभा में इस सप्ताह हंगामे के बीच केवल 66 मिनट

ही कार्यवाही चली।

राज्यसभा में बजट सत्र के पहले सप्ताह 159 मिनट कार्यवाही चली। उच्च सदन में पूरे सप्ताह में 14 मार्च को सबसे अधिक 82 मिनट और 16 मार्च को सबसे कम तीन मिनट बैठक चली। मंगलवार 14 मार्च को राज्यसभा ने ऑस्कर जीतने पर तेलुगु फिल्म

द्वाआरआरआरद्द और तमिल वृत्तचित्र द्वाद एलिफेंट व्हिस्परसंद्द की पूरी टीम को बधाई दी। इसी दिन उच्च सदन में वर्ष 2022-23 के अनुदान की अनुसूचक मांग के दूसरे बैच का दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू कश्मीर की अनुदान की मांग पेश की गई। संसद में जारी गतिरोध और बहुत कम कामकाज होने के बारे में पूछे जाने पर संविधान विशेषज्ञ एवं लोकसभा के पूर्व महासचिव पी डी टी आचारी ने कहा, हंगामा और गतिरोध का होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रयास होना चाहिए कि सत्र हंगामे की भेंट नहीं चढ़े। उन्होंने कहा कि सरकार अपना कामकाज निपटाने के लिए सत्र बुलाती है, ऐसे में सदन चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है। आचारी ने कहा कि अगर सदन में इस प्रकार से शोर शराबा होता है और सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता है तब इसका मतलब है कि सत्ता पक्ष ने अपना दायित्व पूरी तरह से नहीं निभाया है।

वैज्ञानिक श्री अन्न की पैदावार और उपयोगिता बढ़ायें : मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर और खानपान की शैली के कारण होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए वैज्ञानिकों से श्री अन्न (मोटे अनाजों) की पैदावार तथा उपयोगिता बढ़ाने के लिए प्रयास तेज करने का शनिवार को आह्वान किया।

श्री मोदी ने राजधानी के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित 'ग्लोबल मिलेट्स कांफ्रेंस' का उद्घाटन करते हुए कहा कि विश्व जहां जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जुझ रहा है वहीं श्री अन्न विपरीत जलवायु और कम पानी में बेहतर पैदावार देते हैं। रसायन के बिना प्राकृतिक तरीके से भी मोटे अनाजों की पैदावार ली जा सकती है। मोटे अनाजों की फसल अन्य फसलों की तुलना में जल्दी तैयार होती है। इसकी क्षति भी कम होती है और स्वाद में विशिष्टता इसे खास पहचान दिलाती है। खान-पान की शैली से होने वाली बीमारियों को मोटे अनाजों को भोजन का हिस्सा बनाने से रोका जा सकता है। इन अनाजों में रेशे की मात्रा अधिक होती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि चिंता की बात यह है कि खान-पान में मोटे अनाजों का हिस्सा पांच-छह प्रतिशत ही है। इसका उपयोग बढ़े, इसके लिए हर वर्ष इसका लक्ष्य निर्धारित करना होगा। वैज्ञानिकों को इस पर ध्यान देना होगा। कई राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में श्री अन्न को शामिल किया गया है और मिड-डे मील में इसे शामिल किया जा सकता है। उन्होंने



कहा कि 'ग्लोबल फूड सिक्यूरिटी' को लेकर विश्व चिंतित है और मोटे अनाजों को लेकर एक नई व्यवस्था कायम करने तथा दुनिया में आपूर्ति चेन को विकसित करने की जरूरत है।

श्री मोदी ने कहा कि मोटे अनाज सदियों से भारतीय जीवन शैली का हिस्सा रहे हैं और श्री अन्न के मामले में भारत अग्रणी रहा है। वह इस मामले में अपने अनुभवों को विश्व के साथ साझा करना चाहता है और दुनिया से सीखना भी चाहता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण, प्रकृति, स्वास्थ्य और किसानों की आय मोटे अनाजों से जुड़े हैं। श्री अन्न से मोटे अनाजों को एक नई पहचान मिली है, यह

समग्र विकास का माध्यम बना है तथा यह गांव-गरीब से जुड़ा है और छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार है। आज भी आदिवासी समाज के सत्कार में यह शामिल है। उन्होंने कहा कि 12-13 राज्यों में मोटे अनाजों की खेती होती है और घरेलू खपत इसकी प्रतिमाह दो से तीन किलोग्राम थी जो अब बढ़कर 14 किलोग्राम हो गयी है। उन्नीस जिलों में यह 'एक जिला-एक उत्पाद' योजना में शामिल है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मोटे अनाजों को छोटे किसान उगाते हैं जिनकी संख्या देश में लगभग ढाई करोड़ है। सरकार ने ऐसे किसानों की सुध ली है। श्री अन्न का

भारत ने श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का बीड़ा उठाया : तोमर

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व में श्री अन्न को बढ़ावा देने का एजेंडा निर्धारित किया है। ग्लोबल मिलेट्स (श्री अन्न) सम्मेलन में दिल्ली आए विभिन्न देशों के कृषि मंत्रियों की शनिवार को गोलेमेज कांफ्रेंस हुई। इसमें मेजबानी करते हुए श्री तोमर ने अपने उद्घोषण में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व में श्री अन्न को बढ़ावा देने का एजेंडा निर्धारित किया है। श्री अन्न भविष्य के सुपर फूड हैं और भूख, कुपोषण तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में बहुत उपयोगी है। ये फसलें किसानों, उपभोक्ताओं और जलवायु के लिए भी उपयोगी हैं। भारत ने इन उत्कृष्ट अनाजों को वैश्विक स्तर पर भोजन की थाली तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। विभिन्न देशों ने श्री अन्न को बढ़ावा देने की सरकार की पहल की सराहना की और भारत को इस संबंध में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। श्री तोमर ने गोलेमेज कांफ्रेंस में कहा कि श्री अन्न के उत्पादन, उपभोग, मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में विश्व के विभिन्न हिस्सों के प्रतिष्ठित लोगों के सम्मिलन से इसे बढ़ावा देने के प्रयासों को निश्चित ही गति मिलेगी। श्री तोमर ने कहा कि आज का मेगा इवेंट श्री अन्न के उन मूल्यों को प्रदर्शित करता है, जो इतिहास में भुला दिए गए थे। अब श्री अन्न के संवर्धन की गति बढ़ाने के लिए सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष-2023 के लक्ष्यों को प्राप्त करने और भारत को 'मिलेट्स के वैश्विक हब' के रूप में स्थापित करने हेतु किसानों, स्टार्टअप्स, निर्यातकों, खुदरा व्यवसायों, होटल संघों और भारत एवं विदेशों में सरकार के विभिन्न अंगों को शामिल करके एक बहु-हितधारक एंजेजमेंट उपगम अपनाया है।

बाजार बढ़ेगा तो किसानों की आय बढ़ेगी और इससे गांवों को फायदा होगा। देश में 500 से ज्यादा श्री अन्न स्टार्ट-अप बने हैं और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं मिलेट्स के उत्पाद बना रही हैं। इससे पूर्व कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि श्री मोदी वर्षा आधारित खेती करने वाले छोटे किसानों की ताकत बढ़ाना चाहते हैं।

श्री मोदी ने इस अवसर पर एक डाक टिकट और 75 रुपये का एक विशेष सिक्के का अनावरण भी किया। यह सम्मेलन दो दिनों तक चलेगा। इसमें कई देशों के कृषि मंत्री और कृषि से संबंधित विभागों के मंत्री शामिल हो रहे हैं। श्री मोदी ने इस मौके पर मोटे अनाजों पर आधारित एपीडा की ओर से लगायी गयी एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।



CAPF में पिछले तीन वर्षों में 436 जवानों ने की आत्महत्या: सरकार

एनसीआर समाचार

पिछले तीन वर्षों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और असम राइफल्स (अफ) में चार सौ छत्तीस कर्मियों ने आत्महत्या की है। उक्त अवधि के दौरान सीआरपीएफ (154) में सबसे अधिक आत्महत्याएं दर्ज की गईं, जबकि बीएसएफ से 111 आत्महत्याएं दर्ज की गईं, गृह मंत्रालय (MHA) ने बुधवार को राज्यसभा को सूचित किया।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रासंगिक जोखिम कारकों के साथ-साथ प्रासंगिक जोखिम समूहों की पहचान करने और सीएपीएफ और एआर में आत्महत्या और भ्रातृहत्या की रोकथाम के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

द इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स के मुताबिक उप-समूहों के बीच भेदभाव, दुर्व्यवहार का सदमा, कार्यस्थल पर धमकाना, अनुशासनात्मक या कानूनी कार्रवाई शुरू करने का डर, कंपनी कमांडर और जवानों के बीच संचार की कमी कुछ कारण बताए गए थे। सीएपीएफ में आत्महत्या और भ्रातृहत्या के मामलों को देखने के लिए गठित एक टास्क फोर्स द्वारा।

इस टास्क फोर्स का गठन गृह मंत्रालय



द्वारा घटनाओं का अध्ययन और विश्लेषण करने और एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया गया था। जनवरी में गृह मंत्रालय को सौंपी गई अपनी मसौदा रिपोर्ट में, टास्क फोर्स ने तीन प्रमुख कारकों - सेवा की स्थिति, काम करने की स्थिति और व्यक्तिगत / व्यक्तिगत मुद्दों को पाया - जिसके कारण आत्महत्या और भाईचारे की घटनाएं हुईं।

आत्महत्या की घटनाओं का आंकड़ा साझा करते हुए राय ने कहा कि सीआरपीएफ में हुई 154 घटनाओं में से 2020 में 54 जवानों ने आत्महत्या की, 2021 में 57 और पिछले साल 43

जवानों ने आत्महत्या की. उन्होंने कहा, बीएसएफ [सीमा सुरक्षा बल] में आत्महत्या की 111 घटनाओं में से 30 कर्मियों ने 2020 में आत्महत्या की, 44 ने 2021 में और 37 ने 2022 में आत्महत्या की।

उत्कृष्ट केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल] में, 2020 में 18, 2021 में 21 और 2022 में 24 कर्मियों ने आत्महत्या की। जबकि रई [सशस्त्र सीमा बल] में, 18 कर्मियों ने 2020 में आत्महत्या की, 2021 में नौ और पिछले वर्ष 13 कर्मियों ने आत्महत्या की। . ITBP [भारत तिब्बत सीमा पुलिस] में, 2020 में 13 कर्मियों ने,

2021 में 10 और पिछले वर्ष नौ कर्मियों ने आत्महत्या की। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) में रहते हुए, 2020-23 से हर साल दो कर्मियों की आत्महत्या हो जाती है।

आत्महत्या के कारणों में, टास्क फोर्स ने काम के विस्तारित घंटे, आराम और मनोरंजन के लिए अपर्याप्त समय, अन्य क्षेत्रों के अपने समकक्षों की तुलना में, नौकरी से संतुष्टि की कमी, अलगाव की भावना और सामाजिक और पारिवारिक समर्थन की कमी की पहचान की, और कमी दर्ज की। मजबूत शिकायत निवारण तंत्र," मसौदा रिपोर्ट से विवरण का हवाला

देते हुए एक स्रोत ने कहा।

राय ने कहा कि सीएपीएफ, एआर और एनएसजी कर्मियों के बीच आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में सीएपीएफ, एआर और एनएसजी कर्मियों के स्थानांतरण और छुट्टी से संबंधित पारदर्शी नीतियां शामिल हैं। कठोर क्षेत्र में कर्मियों की सेवा के बाद चॉइस पोस्टिंग संभव मानी जाती है। ड्यूटी के दौरान चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती होने की अवधि को ड्यूटी पर माना जाता है

उठाए गए/उठाए जा रहे अन्य कदमों को सुचीबद्ध करते हुए, राय ने कहा, सैनिकों के रहने की स्थिति में सुधार, पर्याप्त मनोरंजन/मनोरंजन, खेल, संचार सुविधाएं आदि प्रदान करना। महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों में क्रेच सुविधा भी प्रदान की जाती है (जहां भी संभव हो) कतिपय दुर्गम क्षेत्रों (परिवार को समायोजित करने के लिए) में पदस्थापित रहते हुए अंतिम पदस्थापन के स्थान पर सरकारी आवास का रख- रखाव, बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ व्यक्तिगत एवं तनाव प्रबंधन का रख-रखाव, मनोवैज्ञानिक चिन्ताओं को दूर करने के लिए विशेषज्ञों से वार्ता करना तथा नियमित रूप से साधना करना और बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग।

मेरठ के एक युवक को मिला बॉलीवुड फिल्म के बाद वेब सीरीज में काम करने का सुनहरा मौका



एनसीआर समाचार

उत्तर प्रदेश: जिला मेरठ के एक छोटे से गांव रोहटा-मीरपुर निवासी अभिनेता महबूब अली को एक और बॉलीवुड फिल्म के बाद वेब सीरीज "मसीहा" में एक किरदार की भूमिका को निभाने का मौका मिला। इसमें मुख्य भूमिका के तौर पर जाने-माने चेहरे बॉलीवुड अभिनेता अक्षय आनन्द, शोएब चौधरी, संवेदना सुवालका और आदि कलाकार काम कर रहे हैं जो पहले काफी फिल्मों और नाटकों में काम कर चुके हैं। इस वेब सीरीज के निमाता शोएब चौधरी हैं जिन्होंने काफी फिल्मों, नाटकों और डॉक्यूमेंट्री को प्रोड्यूस किया हैं इसके डायरेक्टर अरशद खान और कैमरा मेन - दुर्गेश है। काफी बातचीत के दौरान हमें पता चला है कि इसका आधे से ज्यादा भाग उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में ही शूट किया गया, शेष भाग मुंबई में ही शूट होगा। एक्टर महबूब अली ने हमें बताया कि, थियेटर और कैमरा एक्टिंग ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने काम पाने के लिए काफी जगह ऑडिशन दिए, समय लगा पर धीरे- धीरे मुझे काम मिलना शुरू हुआ, लेकिन काम पाने के लिए मैंने अपना धैर्य और आत्मविश्वास नहीं खोया मैं लगातार ऑडिशन देता रहा जिसकी वजह से मुझे उसके परिणाम भी नजर आए।

डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ उद्घाटन

एनसीआर समाचार

डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन हुआ। रिसेंट एडवांसेज इन कैमिकल साइंसेज विषय पर आयोजित संगोष्ठी का श्रुभारंभ कुलपति माननीय प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने किया। मंच पर गौर अतिथि के रूप में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मानस के धोरई, रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष प्रोफेसर एपी मिश्रा,



डायरेक्टर आर एंड डी प्रो हरेल थामस और संयोजक कल्पतरू दास उपस्थित थे । कुलपति प्रो नीलिमा गुप्ता ने देश की प्रगति में विज्ञान के योगदान को याद दिलाते हुए। विश्व

स्तरीय रिसर्च के लिये हरसंभव योगदानकी बात कही, प्रो धोरई ने कहा कि हमें वैज्ञानिक के रूप में समाज के विकास में योगदान देना चाहिये। अतिथियों का स्वागत प्रो विजय वर्मा, डॉ. विवेक तिवारी,

डॉ रबेश दास, डा. नीरज, डा रितु यादव ने किया।आज सेमिनार के तीन सत्रों का समापन हुआ जिसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ और शोध छात्रों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। टेक्निकल सेशन फर्स्ट में चेयरपर्सन प्रो एपी मिश्रा और प्रो अस्मिता गजभिष्ट थे, कीनोट स्पीकर प्रोफेसर एमके धोरई आईआईटी कानपुर,आमंत्रित व्याख्यान प्रोफेसर प्रसन्नजीत मॉल (नाइजर भुवनेश्वर) प्रो ए विसाई (आईसर), प्रो एसएसबी रामशास्त्री (आईसर मोहाली) रहे।

बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से आपूर्ति ठप, कई शहरों में गहराया संकट

एनसीआर समाचार

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि बातचीत का रास्ता खुला है। गुरुवार रात 11 बजे के बाद नेशनल ग्रिड से जुड़े कार्यालय में मामला दर्ज कर व्यवस्था ठप करने का प्रयास करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली आपूर्ति चरमरा गई है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और मेरठ समेत कई शहरों में हड़ताल के पहले ही दिन जबरदस्त संकट खड़ा हो गया। गोरखपुर और कानपुर की फैक्ट्रियों में औद्योगिक उत्पादन ठप हो गया। राजधानी लखनऊ का करीब एक चौथाई बिजली संकट की चपेट में रहा। इस मामले में हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है। उन्होंने कार्यकर्ता नेताओं को तत्बन्ध किया है। वहीं सरकार ने हड़ताल को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। बिजली आपूर्ति बहाल करने में सहयोग नहीं करने वाले कई कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही एंजिनियों के खिलाफ एफआईआर भी



दर्ज कराई थी।

वहीं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने हड़ताली कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि लाइन में गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आपूर्ति को पूरी तरह से नियंत्रण में बताते हुए कहा कि प्रदेश में 4000 मेगावाट सरप्लस बिजली है। दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारी नेताओं को अवमानना नोटिस जारी किया है।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे का दावा है कि हड़ताल के कारण उत्पादन निगम की 1030 मेगावाट क्षमता की 5 इकाइयां ठप पड़ी हैं। राज्य में कुल 1850 मेगावाट उत्पादन प्रभावित हुआ है। समिति ने बिजली कर्मियों पर तोड़फोड़ के आरोपों का जोरदार खंडन किया और कहा कि बिजली संयंत्र बिजली संयंत्रों को अपनी मां मानते हैं और वे शांतिपूर्वक हड़ताल पर

हैं। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि ट्रांसमिशन की कई लाइनें बंद हैं और 33/11 केवी सब स्टेशन से बड़े पैमाने पर आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

संघर्ष समिति ने हड़ताल के लिए बिजली निगमों के शीर्ष प्रबंधन के जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बिजली कर्मचारी ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते का सम्मान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। समिति का दावा है कि 16 मार्च की रात 10 बजे से हड़ताल शुरू होने के बाद से एक भी बिजली मिसत्री जेनरेटिंग हाउस, एसएलडीसी और ट्रांसमिशन पावर सब-स्टेशनों की नाइट शिफ्ट में काम करने नहीं आया है। हड़ताल शत प्रतिशत सफल रही। अराजकता फैलाने वाले कार्यकर्ताओं की होगी सूची: योगी हड़ताली बिजली कर्मचारियों पर सख्ती दिखाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में कहा कि अराजकता फैलाने वालों की सूची बनाई जाएगी। बिजली की फीडर बंद करने वालों के खिलाफ कर्यवाही करने की बात कही।

खुला है संवाद का रास्ता-अरविंद शर्मा

उधर, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि बातचीत का रास्ता खुला है। गुरुवार रात 11 बजे के बाद नेशनल ग्रिड से जुड़े कार्यालय में मामला दर्ज कर व्यवस्था ठप करने का प्रयास करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि यह समय चुनौती का है। सबर रखो। जनप्रतिनिधियों को ध्यान रखना चाहिए कि जो कर्मचारी अपनी सेवाएं देना चाहते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हाईकोर्ट सख्त, 20 को होगी सुनवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में कर्मचारी नेताओं को अवमानना नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लखनऊ को वारंट तामील करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कर्मचारी नेताओं को 20 मार्च को तत्बन्ध किया है। हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि हड़ताल हाई कोर्ट के पुराने आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि बिजली आपूर्ति बाधित नहीं की जानी चाहिए।

कब है रमजान का पहला रोजा, 21 मार्च या 22 मार्च को दिखेगा रमजान का चांद



एनसीआर समाचार

इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोगों के लिए सबसे पवित्र रमजान के महीने की शुरूआत होने वाली है। इस मार्च महीने की आने वाली 22 तारीख को रमजान का चांद का देखा जाएगा और 23 मार्च को पहला रोजा रखा जाएगा। इबादतों के महीने रमजान की शुरूआत शाबान महीने के खत्म होने के बाद दिखने वाले चांद से होती है। बता दें कि, जिस रात को चांद दिखेगा उसी रात की सुबह को पहले रोजे की सेहरी होगी।

22 मार्च को भी हो सकता है पहला रोजा

बता दें कि, इस्लामी कैलेंडर के दिन चांद के इर्द गिर्द घूमते है। कई बार यह महीना 29 दिनों का होता है तो कई बार 30 दिनों का। ऐसे में अगर शाबाद का महीना 29 दिनों का हो तो फिर, रमजान 2023 का पहला रोजा 22 मार्च को होगा। इस वर्ष रमजान का पहला रोजा 22 मार्च का होगा या फिर 23 मार्च का यह बात पूरी तरह से 21 मार्च को ही स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि अगर महीना 29 दिनों का हुआ तो 21 मार्च की शाम को चांद नजर आएगा।

सऊदी अरब में कब है पहला रोजा ?

अगर सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों की बात करें तो बीते दिनों आई खबर के मुताबिक, 23 मार्च का पहला रोजा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो भारत में पहला रोजा 22 मार्च को होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश भारत के मुकाबले एक दिन आगे चलते हैं।

गुजरात के डांग में बच्चियों के साथ हो रहे अपराध मामले में BTTS पार्टी अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने सरकार को दिया आवेदनपत्र



एनसीआर समाचार

गुजरात के डांग में बीते दिन 17 मार्च 2023 को सुबीर तालुका में डांग जिला भारतीय आदिवासी दल द्वारा सूरत में पिछले महीने की गई बलात्कार की घटना के विरोध में इच्छर पार्टी के अध्यक्ष और कार्यकर्ता आरोपी को सजा मिले इस मामले में सुबीर मामलतदारश्री को आवेदनपत्र दिया गया।

डांग जिला भारतीय आदिवासी सेना पार्टी के जिलाध्यक्ष नीलेशभाई झांबरे के मुताबिक, पिछले महीने सूरत जिले के सचिन इलाके के कुपलेटा गांव में एक मुस्लिम युवक ने दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था और फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है। किसे तत्काल फांसी की सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। डांग जिला भारतीय जनजातीय सेना के पार्टी अध्यक्ष द्वारा मांग की गई है कि, भविष्य में ऐसी घटना ना हो। सुबीर तालुका सेवासाधन में आवेदन पत्र सौंपने के लिए अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं, सुबीर तालुका BTTS के अध्यक्ष योगेशभाई बारसा और डांग जिला BTTS के अध्यक्ष नीलेशभाई एस झांबरे के बीच गगनभाई, सोमृभाई, इत्याभाई पवार की विशेष उपस्थिति देखी गई।

डांग में प्रतिस्पर्धा का माहौल, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने में मिशन मंगलम योजना हुई सहायक



एनसीआर समाचार

गुजरात: डांग में घोर प्रतिस्पर्धी माहौल के बीच, डांग जिले के सवारदा जैसे दूरदराज के इलाकों की लड़कियां, जो मुश्किल से माध्यमिक शिक्षा पूरी कर पाईं। मिशन मंगलम जैसी योजनाओं की मदद से आत्मनिर्भर और घर में कार्यरत हो गई हैं। ऐसा सुबीर तालुका के सावरदा गांव की किंजल सखी मंडल की रबीना गावित ने कहा पिछले साल ही गांव की करीब दस युवतियों ने एकत्र होकर सखी मंडल का गठन किया था। तुरंत ही वह मशरूम उत्पादन और डांग जिला पापड़ बनाने सहित शिवांकाम में प्रशिक्षण से लैस हो गई और गाँवों में शिवांकाम के साथ-साथ शिवांकाम में अन्य जरूरतमंद बहनों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया।

सिलाई ब्लाउज और ड्रेस के साथ-साथ अपना कपड़ा बेचकर भीतरी इलाकों की आदिवासी लड़कियां आराम से दस से बारह हजार रुपये महीना कमा रही हैं। इस वजह से खुद की रोजी-रोटी की चिंता करने वाली बहनें अन्य युवतियों को भी प्रशिक्षण और रोजगार दे पाई हैं। डांग जिले के सुबीर तालुका में ऐसे 1116 सखी मंडल और 66 सखी संघ बहुत सफलतापूर्वक प्रगति कर रहे हैं। डांग जिले की ग्रामीण महिलाएं वास्तव में आत्मनिर्भर बन गई हैं, जो कई आर्थिक उत्पादन गतिविधियों के साथ-साथ बचत और ऋण गतिविधियों में संलग्न हैं, जो पलायन जैसे मुद्दों से जुझ रहे डांग जिले के पूर्वी क्षेत्र के इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो रहा है।

संपादकीय

राज्यपाल फिर सवालिया

सर्वोच्च अदालत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने राज्यपाल की भूमिका, दायित्व और सदन में बहुमत साबित करने के आदेश सरीखे पहलुओं पर एक तार्किक बहस को सुना है और सभी पक्षों को सचेत भी किया है। बुनियादी संदर्भ महाराष्ट्र के अघाड़ी गठबंधन की सरकार का है। चूँकि शिवसेना में विधायकों के एक बहुमती गुट ने बगावत की थी, नतीजतन तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन राज्यपाल के हस्तक्षेप से बगावती गुट और भाजपा ने साझा तौर पर सरकार बना ली। आज वही सरकार कार्यरत है। उद्धव ठाकरे गुट के वकीलों ने ऐसी सरकार को ‘असंवैधानिक’ करार दिया है, जबकि न्यायाधीशों का सवाल है कि उस सरकार को कैसे बहाल किया जा सकता है, जिसके मुख्यमंत्री ने सदन में बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था? बहरहाल संविधान पीठ ने दोनों पक्षों के तर्क सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन राज्यपाल की भूमिका एक बार फिर सवालिया हुई है।

महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस्तीफा देकर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब रमेश बैस नए राज्यपाल हैं। इसके अलावा, तेलंगाना राज्यपाल को भी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी है। वहां राज्यपाल ने बीते सितंबर से 7 पारित विधेयकों को स्वीकृति नहीं दी है। वह विधानसभा में पारित बजट पर भी मुहर नहीं लगा रही हैं। यह उनका जानबूझ कर किया जाने वाला व्यवहार है। यकीनन यह असाधारण, संविधान से इतर स्थिति है। संविधान ने इस संदर्भ में राज्यपाल के विशेषाधिकारों की स्पष्ट व्याख्या नहीं की है। राज्यपाल किसी भी समय-सीमा तक बिलों पर कुंडली मार कर बैठ सकते हैं। यह कौन-सी संवैधानिक शक्ति हुई? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और गवरनर बनावरी लाल पुरोहित का विवाद भी सर्वोच्च अदालत में है। शीर्ष अदालत की टिप्पणी है कि आपसी बातचीत का स्तर बिल्कुल निचले स्तर तक नहीं ले जाना चाहिए। दोनों संवैधानिक पदों के बीच ऐसी होड़ नहीं लगनी चाहिए। बहरहाल तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में भी ‘मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल’ की स्थितियाँ हैं। उत्तराचल बेहद गहरे हैं, जबकि विवाद संवैधानिक नहीं हैं। दोनों पदों के बिना हमारा संघीय ढांचा कारगर ही नहीं हो सकता। विडंबना और दुर्भाग्य है कि राज्यपाल विपक्षी दलों की सरकारों वाले राज्यों में ही ‘प्ररोक्ष राजनीति’ खेलते देखते हैं। दरअसल हमारी सियासत को एहसास होना चाहिए कि अब ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेशी भारत नहीं है। भारत आज स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक संविधान वाला देश है। राज्यपाल की भी एक निश्चित और संवैधानिक भूमिका है। एक उदाहरण चुनाव आयोग के फैसले और अनुशास का है। आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री को लेकर अपना फैसला बंद कवर में राज्यपाल को भेजा था। तत्कालीन महामहिम ने करीब 6 माह तक उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया।

चुनावी साल: ऐसे वादें मानो धरती पर स्वर्ग उतार लाएंगे

-योगीराज योगेश-

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट में लाडली बहनों के लिए 1000 रुपए देने का प्रावधान किया तो बिना देरी किए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा कर दी। गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के भाव कम करने हों या फ्री में बिजली, पानी, इलाज और राशन मुधैया करने का मामला हो। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत सभी राजनीतिक दल हर घोषणाएँ पूरी करने के वादे कर रहा है। एक से बढ़कर एक घोषणाएँ। भिंडी मार्केट में जैसे सब्जी के लिए बोली लगाई जाती है वैसा ही नगरा प्रदेश में दिखाई दे रहा है। लोकलुभावन घोषणाएँ करने की होड़ लगी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव के बाद ये नेता धरती पर स्वर्ग उतार ही जाएँगे।

सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की : कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी की यात्रा के बाद मिले थोड़े से मोमेंटम को कैसे लुप्त किया जाए, इसके प्रयास में प्रदेश कांग्रेस के नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का मसला हो या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का मुद्दा। कांग्रेस नेताओं के सुर एक जैसे नहीं है। सब अपनी डफली अपना राग की तर्ज पर कोरस गाने के प्रयास में है। गुटबाजी की बात यह यदि थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दी जाती तो जनता से लोक लुभावने वादे और घोषणाएँ करने के मामले में भी पार्टी नेताओं के बीच एकजुटता का अभाव साफ दिख रहा है। कमलनाथ जी कह रहे

-रमेश सर्राफ धमोरा-

राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने में कुछ महीनों का ही समय शेष रह गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी-अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। कांग्रेस में चल रहा नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा भी खत्म सा हो गया है। यह तय हो गया है कि अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उनके प्रतिद्वंदी सचिन पायलट ने भी अब मान लिया है कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का समय निकल चुका है। इसीलिए उनकी नेतृत्व परिवर्तन की मांग भी बंद हो गई है। अब सचिन पायलट कहने लगे हैं कि पार्टी के सभी लोगों की एकजुटता से ही अगला विधानसभा चुनाव जीता जा सकता है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मालूम है कि सरकार चाहे कितने ही विकास के कार्य करवायें। जनता हर पांच साल के बाद सत्ता बदल देती है। राजस्थान के लोगों का मानना है कि सत्ता बदलने से प्रेश में और अधिक तेजी से विकास कार्य होते हैं। अशोक गहलोत ने अपने पांच साल के कार्यकाल में सचिन पायलट को तो मात दे दी है। मगर अब उनके समक्ष विधानसभा

भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश का अपमान किया है। गौरतलब है कि संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है। संसद में जो हुआ उसे पुरी दुनिया ने देखा। सवाल यह है कि जब केंद्र सरकार राहुल के बयान को इतना गंभीर मानती है तो उनके खिलाफ देश के अपमान और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराती। इसका फैसला अदालत कर लेगी कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है या नहीं।

-योगेंद्र योगी-

आजादी के बाद देश के संसदीय इतिहास में ऐसा पहला मौका आया जब सत्तारूढ़ दल ने संसद ठप की हो। संसद की यह कार्यवाही कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी से माफी मंगवाने की मांग को लेकर बाधित रही। संसद सत्र का प्रति मिनट खर्चा ढाई लाख रुपए आता है। अर्थात एक दिन भी यदि संसद की कार्यवाही ठप रहती है तो करोड़ों का नुकसान होता है। इसकी भरपाई सांसद या मंत्री नहीं करते, बल्कि देश के आम करदाताओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। राहुल ने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में भाग लेते समय संस्थाओं के नियंत्रण में होने और अपने फोन की जासूसी किए जाने का आरोप लगाया। राहुल ने अपने ऊपर आपराधिक मामले दर्ज कराए जाने का मुद्दा उठाया। आरएसएस को एक फासीवादी संगठन और भारत में मीडिया और न्यायपालिका नियंत्रण में बताते हुए विदेशी हस्तक्षेप की मांग की।

भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश का अपमान किया है। गौरतलब है कि संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है। संसद में जो हुआ उसे पुरी दुनिया ने देखा। सवाल यह है कि जब केंद्र सरकार राहुल के बयान को इतना गंभीर मानती है तो उनके खिलाफ देश के अपमान और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराती। इसका फैसला अदालत कर लेगी कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है या नहीं। इससे भाजपा का बचना यह दशातों है कि देश के अपमान और देशद्रोह को सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। हकीकत में इस मामले में भाजपा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवा रही है। सवाल यह भी है कि भाजपा राहुल गांधी से तो चुनावी तर्कों से निपट लेगी किन्तु वैश्विक संस्थाओं द्वारा विभिन्न मामलों में देश की हालत की जो तस्वीर बताई गई है, भाजपा उससे कैसे निपटेगी। भाजपा ने ऐसी संस्थाओं से कभी माफी मांगने और उन देशों को चेतावनी देते हुए संबंधों में दारार पड़ने की



बात कभी नहीं की।

अलबत्ता केंद्र सरकार उन रिपोर्टों को भारत की छवि खराब करने वाले बताता हुए खारिज करती रही है। विगत वर्षों में संयुक्त राष्ट्र सहित विश्व स्तर की रैंकिंग प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं की रिपोर्ट में भारत की जो तस्वीर पेश की है, वह देश को शर्मसार करने वाली रही है। केंद्र की भाजपा सरकार विश्व में विभिन्न मामलों में जारी रिपोर्टों को खारिज तो कर सकती है, पर माफी नहीं मंगवा सकती, जिनके कारण भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत छह पायदान नीचे खिसक कर अब 121 देशों में शामिल किया है या नहीं। इससे राष्ट्र के वार्षिक सूचकांक में वर्ल्ड हैपीनेस इंडेक्स में शामिल कुल 146 देशों में भारत 136वें पायदान पर है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की ओर से जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत 142वें स्थान पर बरकरार है। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टालरेंस का दंभ भरने वाली सरकार की हड़ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2021 में वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में भारत का स्थान 85वां रहा। मानव विकास सूचकांक में पिछले वर्ष भारत 131वें

महाराष्ट्र मामले में ऐतिहासिक होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला

-सनत जैन-

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित सभी पक्षों की सुनवाई पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की खंडपीठ ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता कपिल सिब्बल, ए एम सिंघवी, देवदत्त कामत एवं अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने अपने पक्ष को सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से रखा है। संविधान पीठ के न्यायाधीशों ने भी समय-समय पर जिन सवालों को किया, उससे स्पष्ट लग रहा है, राज्यपाल की भूमिका सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उपयुक्त नहीं माना। जिन सदस्यों ने दलबदल किया था, उनके दलबदल से संबंधित मामले विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित थे। सुप्रीम कोर्ट का यह भी मानना था, कि राज्यपाल की सी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। साथ ही बहस के दौरान यह भी राय देखने को मिली, कि जब उद्धव ठाकरे ने खुद ही फ्लोर टेस्ट के पहले अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट कैसे उस सरकार को बर्खास्त कर सकती है। 9 दिन चली इस बहस में कई राज्यों में हुए दलबदल के बाद चुनी हुई बहुमत वाली सरकारों में परिवर्तन हुआ है। इन सभी में राज्यपालों की भूमिका को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों ने अपना पक्ष रखा। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में बड़ी तेजी के साथ दलबदल कर हर राज्य में चुनी हुई सरकार को गिरा कर दलबदला करके आए दलबदलुओं के समर्थन से सरकारें बनी है। उसको लेकर दल बदल कानून, पार्टी के विहंग, सांसद अथवा विधायक को पार्टी के सिंबल से चुना जाता है। ऐसी स्थिति में जब वह अपनी पार्टी छोड़ता है, तो क्या वह उसका अधिकार है। क्योंकि उसने पार्टी से चुनाव लड़ा और व्यक्तिगत राय को बनाते हुए दलबदल किया। ऐसे कई जटिल प्रश्नों के जवाब और सवाल सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने जिस तरह से मामले के सभी पहलुओं को जानने की कोशिश की है। सभी पक्षों से सभी पहलुओं पर राय ली है। उसके बाद ऐसा लगता है, कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बड़ा ऐतिहासिक होगा। इस फैसले में राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है। दल बदल करने वाले विधायक समूह में दल बदल करके, तो सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देकर पुनः चुनाव लड़ने, यदि पूरी पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करती है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक हो सकता है. पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में दल बदल के माध्यम से कई निर्वाचित सरकारों को अल्पमत की सरकार बनाकर गिराया गया। दल बदल के बाद एक पार्टी विशेष की सरकारें बनी। इसमें कई तरह के आरोप, विशेष रूप से राज्यपाल की भूमिका, पैसे को लेकर ईडी अथवा सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर दल बदल कराने की बात भी सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान सामने आई है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मामले को जिस तरह से ग्रहण किया है। उसके बाद पर्याप्त कारण है, कि राज्यपाल की भूमिका तय होगी। यदि किसी पार्टी के कुछ विधायक या सांसद दलबदल करते हैं। ऐसी स्थिति में सदन के अध्यक्ष की दल बदल कानून में मिली शक्तियां पार्टी के चुनाव चिन्ह से से चुने गए निर्वाचित प्रतिनिधि के पार्टी के प्रति और निजी अधिकार को लेकर यह फैसला बड़ा मार्गदर्शी हो सकता है। विधि क्षेत्रों और राजनीतिक हलकों में महाराष्ट्र के इस मामले को लेकर बड़ी जिज्ञासा, फैसले को लेकर बन गई है। सभी लोग बातचीत में यह मानते हैं, कि यह फैसला ऐतिहासिक होगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दल बदल कानून के बाद यह माना गया था, कि सरकारों को स्थिर बनाया जा सकेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में अब यह फैसला एक नया दृष्टिकोण और दल बदल कानून में जो बिगंति है। उसको समायत करने में महत्वपूर्ण होगा।

के ताजा बजट सत्र में जीतू पटवारी ने जिस आक्रामक अंदाज में सरकार पर हमला बोला और उसके बाद जो अग्रिय स्थिति विधानसभा में निर्मित हुई वह शर्मसार कर देने वाली है। माननीय सदस्यों द्वारा नियम पुस्तिकाएं फाड़ी गईं। किताबें फेंकी गईं और एक दूसरे पर खुल्लम-खुल्ला बाहें चढ़ाकर ऐसे शब्द बोले गए कि अध्यक्ष को विलोपित करने पड़े। विपक्ष ने अध्यक्ष पर भेदभाव करने का आरोप लगाया और अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए।

अब अविश्वास प्रस्ताव का गिरना या वापस लेना तो तय है ही, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर केवल 48 विधायकों ने ही हस्ताक्षर किए हैं। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि खुद कमलनाथ जी ने इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में दस्तखत नहीं किए। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मामले में कांग्रेस नेता ही एकजुट नहीं हैं। लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि सदन में ऐसी जल्दबाजी, हड़बड़ी और घबराहट क्यों। पार्टी नेता एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में क्यों लगे हुए हैं? क्या जीतू पटवारी की आक्रामकता और सक्रियता से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में बेचैनी है? क्या विधानसभा में हंगामे का लाभ जीतू पटवारी को मिलता देख जानबूझकर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? ताकि यह बताया जा सके कि जीतू पटवारी ने जो मुद्दे उठाए हैं वह पटवारी के नहीं बल्कि कांग्रेस के मुद्दे हैं। और इन मुद्दों पर कांग्रेस एकजुट है। बहरहाल कांग्रेस भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के आपसी सामंजस्य व तालमेल के बाद अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने की रणनीति पर काम किया जा रहा

संबल प्रदान किया है। जिसका लाभ उन्हें चुनाव में मिलना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री बनते ही गहलोत ने उक्त सभी लोगों को मिलने वाली पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की थी।

अपने विकास के एजेंडे के तहत ही मुख्यमंत्री गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। इस नहर परियोजना के पूरा होने से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लोगों को पीने का पानी तो मिलेगा ही साथ ही दो लाख 80 हजार हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के लोगों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बनी हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस परियोजना को केंद्रीय एजेन्डट घोषित कर पूरा करवाने की बात कही थी। मगर केंद्र सरकार ने इस परियोजना को आज तक अपने हाथ में नहीं लिया है। इसी मुद्दे को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं।

आवश्यक सूचना

एनसीआर समाचार के समस्त पाठकों तथा पत्र के साथ जुड़े समस्त पत्रकारों, व्यावसायिक संयोजक, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं/संस्थानों को यह सूचित किया जाता है कि गत वर्षों से श्री बलवीर सिंह के नेतृत्व व स्वामित्व में चले आ रहे वर्तमान एनसीआर समाचार पत्र का प्रकाशन व स्वामित्व मो. हनीफ, पुत्र श्री इस्माईल खान मास्टरजी, संगम विहार के स्वामित्व व नेतृत्व में हो रहा हैं। अतः भविष्य में समस्त प्रकार की व्यावसायिक, कानूनी एवं सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु मो. हनीफ/ नये कार्यालय जी 12/276, संगम विहार, नई दिल्ली - 110062, दुर्भाष (मोबाईल) 8888883968, 9811111715 से सम्पर्क करें

—रोगी को प्रोत्साहित करने के लिए परिवार का साथ भी बेवद जरूरी है। यदि घर में ही खाने-पीने और व्यायाम के हेतु भी माहौल हो तो इससे तालमेल बिठाने में अधिकार प्रशिक्षण सहायक नर्सों परिवार का कोई सदस्य वॉक पर या जिम में रोगी का साथ दे सकता है।

—टेलीविजन देखने दौरान खाते रहना भी डाइजेशन को आमंत्रण दे सकते हैं। इस दौरान न तो हमें अपने खाने की मात्रा का ध्यान रहता है और न ही इस बात का कि हम क्या खा रहे हैं?



सोनाली कुलकर्णी के बयान पर भड़की उफ़ी जावेद



टीवी अभिनेत्री उफ़ी जावेद हमेशा अपने बयानों के लिए चर्चा में रहती हैं। इसी बीच उफ़ी जावेद अब फिर अपने नए बयान से चर्चा में आ गई हैं। एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी के हालिया वीडियो पर उफ़ी जावेद ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा है कि लड़कियों को मांगने का अधिकार है। सोनाली कुलकर्णी का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्ट्रेस लड़कियों के बढ़ते डिमांडिंग नेचर और लड़कों पर बढ़ते दबाव के बारे में बात करती हैं। इस वीडियो पर उफ़ी ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उफ़ी ने कहा कि लड़कियों को मांग करने का अधिकार है।

सोनाली कुलकर्णी के वीडियो को एक तरफ जहां कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर सोनाली को खूब ट्रोल भी किया जा रहा है। अब उफ़ी जावेद ने ट्विटर पर सोनाली के वीडियो को रीट्वीट करते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने लिखा, "आपने जो कहा वह बेहद असंवेदनशील है। आप आज की मॉडल महिलाओं को आलसी कह रही हैं... आज की युवा महिलाएं सिर्फ अपना काम ही नहीं घर भी संभाल रही हैं। इसमें गलत क्या है? अगर वह सोचती हैं कि उसका पति अच्छा कमाने वाला होना चाहिए तो इसमें क्या परेशानी है। सदियों से पुरुषों ने महिलाओं को केवल बच्चे पैदा करने वाली मशीन के रूप में माना है और शादी का सबसे महत्वपूर्ण कारण देहेज है। उन्होंने कहा- लड़कियों, आप पूछने या मांगने से बिल्कुल न डरें। एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी ने इस वायरल वीडियो में कहा, "भारत में बहुत सी लड़कियां आलसी होती हैं, उन्हें ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए या पति चाहिए जिसके पास अच्छी नौकरी हो, जिसके पास घर हो... जिसे सेलरी मिलना तब हो। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अपने घर में ऐसी महिलाएं पैदा करें जो सक्षम हों। जो खुद के लिए कमा सकें.... जो हर खर्च का आधा हिस्सा उठा सकें।"

कंगना से कोई 'प्रॉब्लम नहीं': तापसी पन्नू



बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू का कहना है कि कंगना रनौत अच्छी अभिनेत्री हैं और उनसे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंगना की बहन रंगोली के तापसी को कंगना की 'सस्ती कॉपी' कहे जाने के बाद दोनों के बीच झगड़ा काफी बढ़ गया था। तापसी ने कंगना और उनकी बहन रंगोली द्वारा उन पर किए गए 'सस्ती कॉपी' वाली कमेंट के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वह कंगना के कमेंट और इस बारे में बात करने के बाद शॉकड थीं उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं नहीं जानती, लेकिन यदि कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां वह मेरे सामने होती हैं तो मैं जाकर हैलो कहूंगी। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम उसे है तो उसकी मर्जी। तापसी पन्नू ने कहा, मैं सच बताऊं तो अब मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता। शुरूआती दौर में मुझे इस तरह के कमेंट से फर्क पड़ता था लेकिन अब ऐसी बातों से परेशान नहीं होती। तापसी ने कंगना की तारीफ करते हुए बताया कि वह बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं।

‘बरजख’ में फिर साथ फवाद खान और सनम सईद

फवाद खान और सनम सईद अभिनीत फैमिली ड्रामा बरजख का पहला पोस्टर फ्रांस में होने वाले सीरीज मेनिया फेस्टिवल में जारी किया गया, यहाँ शो का ग्लोबल प्रीमियर होने वाला है। सीरीज मेनिया फेस्टिवल में इसके वर्ल्ड प्रीमियर से पहले, जिंदगी ओरिजिनल शो बरजख के निमाताओं ने फ्रांस के शहर लिले में शो के पोस्टर का अनावरण किया, जिसमें अभिनेता फवाद और सनम ने अभिनय किया था।

बरजख का निर्देशन समीक्षकों द्वारा प्रशंसित निर्देशक असीम अब्बासी द्वारा किया गया है, जिन्होंने जिंदगी की पहली ओरिजिनल चुरेल्ल और फीचर फिल्म केक का भी निर्देशन किया था। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले लेखक-निर्देशक असीम अब्बासी, अभिनेता सनम सईद और निमाता शैलजा केजरीवाल थे। बरजख को साउथ एशिया से चुनी गई एकमात्र सीरीज होने का विशिष्ट सम्मान प्राप्त है। सीरीज शोकेस के इंटरनेशनल पैनोरमा लाइन-अप सेक्शन में दिखाई जाएगी, जहां इसे बेस्ट सीरीज, डायरेक्टर, एक्ट्रेस, एक्टर, स्टूडेंट जूरी और ऑडियंस अवॉर्ड जैसी श्रेणियों में नामित किया गया है।

बरजख एक फैमिली ड्रामा है। सीरीज में फवाद खान एक सिंगल पैरेंट का रोल कर रहे हैं, जो आकर्षक है, लेकिन साथ ही वह किसी चीज के लिए अपराध बोध के तले दबे हुए है, जिसे उन्होंने खो दिया है। फवाद ने कहा, हमारे सीरीज मेनिया प्रीमियर के साथ मेल खाते हुए हमारा पोस्टर जिसे



अब हम दुनिया के सामने पेश करते हैं, इस बात की शुरूआती झलक पेश करता है कि सीरीज अस्पष्टता से क्या उम्मीद की जा सकती है जो आधुनिक दुनिया के बाद के मानव संबंधों को नेविगेट करने में जटिलताओं को दर्शाती है। सनम सईद ने कहा, सीरीज मेनिया फेस्टिवल में भाग लेना वास्तव में किस्मत की बात है। बरजख एक ऐसी कहानी है जिसे मैंने उस

समय से जोड़ा जब मैंने इसे सुना और असीम अब्बासी द्वारा कहानी को गढ़ा गया, जो प्यार और जीवन में हमारे विश्वास को नवीनीकृत करेगी। इसने मुझे न केवल चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया बल्कि मुझे जीवन को एक अलग रोशनी में देखने के लिए प्रेरित किया। हमने स्क्रीन पर जो देखा है, यह उससे बहुत अलग है और सभी अभिनेताओं ने बेहद अलग और विविध भूमिकाएं निभाई हैं।

रवीना टंडन ने नॉर्वेजियन ग्रुप के साथ टिप टिप बरसा पानी को किया रीक्रिएट

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन नॉर्वेजियन डॉस ग्रुप विवक स्टाइल के साथ अपने आइकोनिक नंबर टिप टिप बरसा पानी पर डॉस करती नजर आईं। विवक स्टाइल ने इंस्टाग्राम पर रवीना के साथ डॉस करते हुए एक वीडियो शेयर किया। ग्रुप सांग की धुन पर थिरकना शुरू करता है, जबकि एक्ट्रेस बाद में उन्हें ज्वाइन करती है। विवक स्टाइल ने पोस्ट को कैप्शन दिया: जब आप ओरिजनल के साथ डॉस करते हैं, तो यह सबसे अलग होता है।

ट्रैक 1994 की फिल्म मोहरा का है, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेठ्टी और रवीना टंडन ने अभिनय किया था। इसे उदित नारायण और अलका यागनिक ने गाया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता पाई, और हम आपके हैं कौन के बाद उस साल की यह दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई।



वर्कफ्रंट की बात करें तो, रवीना अगली बार बिनाॅय गांधी द्वारा निर्देशित घुड़चढ़ी में दिखाई देंगी। इसमें पार्थ समथान, खुशाली कुमार और अरुणा ईरानी के साथ संजय दत्त और रवीना टंडन प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

फिल्म ‘नाम बदनाम’ का फर्स्ट लुक के साथ धमाकेदार ट्रेलर हुआ आउट

भोजपुरी फिल्म जगत की मशहूर निर्देशक विष्णु शंकर बेलु और सुपर हॉट एक्ट्रेस काजल राघवानी की फिल्म 'नाम बदनाम' का फर्स्ट लुक के साथ धमाकेदार ट्रेलर जारी हो गया है। इस फिल्म में काजल राघवानी के साथ मुख्य भूमिका में अभिनेता गौरव झा हैं। जिसमें काजल राघवानी का किरदार आपको उलझन में डाल सकती है। 'नाम बदनाम' में काजल राघवानी की भूमिका डायना नामक दबंग गैंगस्टर की है, वहीं ट्रेलर के दूसरे हिस्से में उनकी भूमिका कई शेड्स में नजर आती है।

फिल्म 'नाम बदनाम' का निर्माण कार्जुस प्रालि के बैनर से हुआ है और इस फिल्म का ट्रेलर इंटर 10 रंगीला के ऑफिशियल यूट्यूब



चैनल से रिलीज किया गया है। फिल्म के निमाता शिवम गोयल और शब्बा गोयल हैं। निर्देशक विष्णु शंकर बेलु हैं, जिन्होंने कहा कि नाम बदनाम की पटकथा एक्शन और

इमोशन प्रधान है। फिल्म के ट्रेलर को रिलीज के बाद दर्शकों से अच्छा रिसांस मिल रहा है। हमने एक शानदार फिल्म बनाई है जो दर्शकों को खूब पसंद आएगी। इस फिल्म की

करण जौहर ने अपनी मां के जन्मदिन पर लिखा नोट

करण जौहर ने अपनी मां हीरू जौहर के 80वें जन्मदिन के मौके पर एक नोट लिखा है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी मां के साथ कुछ नई और पुरानी तस्वीरें साझा कीं और लिखा कि कैसे वह उनकी फैशन गार्डियन हैं और कैसे उन्होंने अपने जुड़ाव बच्चों रूही और यश जौहर को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कई तस्वीरें साझा कीं, जिनमें से कुछ उनके हाल के केक काटने के समारोह से लेकर उनके और स्वर्गीय फिल्म निमाता पिता यश जौहर के साथ उनके बचपन की तस्वीरें हैं।

तस्वीरों को शेयर करते हुए करण ने लिखा, मेरी बहादुर और सहनशील मां आज 80 साल की हो गईं... उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे प्यार करना है... मैं जिस चीज में विश्वास करता हूँ, उसके लिए कैसे खड़ा होना है... अगर मैं सही हूँ तो कभी माफी नहीं मांगना या खुद को सही ठहराना नहीं... मैं तुमसे प्यार करता हूँ मां... मैं तुम्हारे बिना रूही और यश को कभी नहीं पाल पाता...

मलाइका अरोड़ा, अनन्या पांडे, तनिषा मुखर्जी से लेकर तुषार कपूर तक सभी ने हीरो आंटी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। शिल्पा शेठ्टी ने लिखा, प्यारी आंटी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, उनके और अधिक प्यार और अच्छे स्वास्थ्य की कामना।



करण स्वर्गीय यश जौहर और हीरू जौहर के इकलौते बेटे हैं। फिल्म निमाता 2017 में सरोगेंसी के जरिए पिता बने थे। और तब से, वह अपनी मां के साथ उनका पालन पोषण कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मां का नाम उलटकर अपनी बेटी का नाम रूही रखा। उनके बेटे का नाम उनके स्वर्गीय पिता यश जौहर के नाम पर रखा गया है।

सबसे खास बात यह है कि इसकी लीड एक्ट्रेस काजल राघवानी का लुक अब तक सबसे अलग है। इस लुक में अंडरवर्ल्ड की सरगना लगती हैं। वहीं फिल्म में गौरव झा खाकी वर्दी में नजर आते हैं जो डायना यानी काजल राघवानी से लोहा लेते दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों की जंग दिलचस्प होने वाली है जो आपको जल्द ही सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी।

फिल्म में काजल राघवानी और गौरव झा के साथ देव सिंह, हीरा यादव और खुद विष्णु शंकर बेलु भी मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। फिल्म का म्यूजिक स्वर्गीय धनंजय मिश्रा का है। डीओपी देवेन्द्र तिवारी हैं। कोरियोग्राफर रिकी गुप्ता है। स्टोरी मनोज कुशवाहा का है। पोस्ट प्रोडक्शन आई फोकस स्टूडियो में हुआ है।